सुस्ती बरकरार: चुने गए किसी भी गांव के लिए अब तक नहीं बनी एक भी योजना

दैनिक जागरण
05-01-16

अटक गई है सांसद आदर्श ग्राम योजना

एस ए शाद, पटना

सांसद आदर्श ग्राम योजना फाइलों में अटक कर रह गई है। एक साल से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद योजना के तहत बिहार में चुने गए गांवों के विकास के लिए एक भी स्कीम नहीं बन पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को आरंभ की गई इस योजना के तहत प्रदेश के 53 गांव चिह्नित किए गए हैं, जिन्हें 2016 तक मॉडल गांव बनाने का लक्ष्य है।

सूत्रों ने बताया कि किसी भी सांसद ने गोद लिए अपने गांव के लिए अब तक कोई राशि नहीं दी है। न ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई रकम मिली है। योजना का संचालन राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है। विभाग का मानना है कि जब तक अलग से राशि का इंतजाम नहीं होता, इन गांवों के लिए किस तरह से योजना बनाई जा सकती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं, उनके अनुसार प्रदेश में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से ही चयनित गांवों का विकास किया जाना है। अतिरिक्त संसाधन के लिए कारपोरेट सेक्टर से संपर्क करना है, लेकिन प्रदेश में बड़े उद्योग के नहीं रहने के कारण कारपोरेट सेक्टर की यहां मौजूदगी भी नगण्य है।

राशि की समस्या को लेकर पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिल चुके राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में गाइडलाइन में कुछ संशोधन कर सकती है। ऐसे राज्य, जहां उद्योग नहीं हैं, उन्हें इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार अलग से राशि दे सकती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए सबसे पहले प्रदेश में भाजपा सांसद छेदी पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम स्थित मलहीपुर का चयन किया था। तब उन्होंने कहा था कि इस गांव में एक भी व्यक्ति मैट्रिक पास नहीं है, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। गांव के लोग पास के जंगल से लकड़ी काटकर लाते हैं और उसे बेच कर अपने लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ही और कई गांव पिछड़े हैं, ग्रामीण विकास की आस में टकटकी लगाए हैं।

बिहार में लोकसभा के 40 तथा राज्यसभा के 13 सदस्यों द्वारा गांवों का चयन किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राशि कर्णांकित नहीं होने और सांसदों से राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण योजना के सफल क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

– श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री

11 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुई है योजना। प्रथम चरण में 2016 तक चुने गए एक गांव को मॉडल गांव बनाना है। फिर हर सांसद को दो और गांवों को 2019 तक मॉडल गांव बनाना है

बिहार के कुछ प्रमुख सांसदों द्वारा चुने गए गांव

▸▸ रामविलास पासवान	भगवानपुर, अकबरमलाही प्रखंड
▸▸ रविशंकर प्रसाद	अलवलपुर, फतुहा प्रखंड
▸▸ धर्मेंद्र प्रधान	लखानीबीघा, दानापुर प्रखंड
▸▸ रामकृपाल यादव	सोनमई, धनरूआ प्रखंड
▸▸ उपेंद्र कुशवाहा	नासरीगंज, अमियावर प्रखंड
▸▸ राजीव प्रताप रूडी	रिवीलगंज, सिताबदियारा प्रखंड
▸▸ चौधरी महबूब अली कैसर	सिमरी बख्तियारपुर, सितनाबाद उत्तरी प्रखंड

देश में चुने गए 679 गांव, बिहार में 53 का हुआ चयन